

गेल और पेट्रोन ने बायो-एथलीन संयंत्र के लिए समझौता किया



नई दिल्ली (वि)। गेल (इंडिया) लिमिटेड और पेट्रोन साइंटेक इंक (पेट्रोन) ने भारत में अपनी डाउनस्ट्रीम इकाई के साथ 500 किलो टन प्रतिवर्ष (केटीए) बायो-एथलीन संयंत्र की स्थापना की संभावना तलाशने के लिए समझौता किया है। यह 50:50 संयुक्त उद्यम (जेवी) मोड में संयंत्र में उत्पादित बायो-एथेनॉल पर आधारित होगा। गेल के कार्यकारी निदेशक (व्यापार विकास और अन्वेषण एवं उत्पादन) सुमित किशोर और पेट्रोन के सीईओ योगी सरीन ने गेल के निदेशक (व्यापार विकास) राजीव कुमार सिंघल की उपस्थिति में गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर बुधवार को हस्ताक्षर किए।

तैयारी | प्राकृतिक गैस के उपयोग का बढ़ाया जाएगा दायरा, सिटी गैस वितरण नेटवर्क की स्थापना होगी यूपी के हर शहर में बनेंगे गैस आपूर्ति स्टेशन

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी में प्राकृतिक गैस के उपयोग का दायरा बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए 'सिटी गैस वितरण नेटवर्क' की स्थापना होगी। घरेलू उपभोक्ताओं को पीएनजी व वाहन चालकों का सीएनजी उपलब्ध कराने को सभी शहरों में 'गैस आपूर्ति स्टेशन' बनेंगे। इसके लिए सभी डीएम से जरूरी कार्रवाई करने को कहा गया है। केंद्र सरकार 2030 तक वन नेशन वन ग्रिड के जरिए देश भर में इस तरह का सिटी गैस वितरण स्थापित करने का काम कर रही है।

इस संबंध में औद्योगिक विकास विभाग ने आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सिटी गैस वितरण परियोजना की स्थापना की महत्ता को देखते हुए प्रदेश में सिटी गैस वितरण



15 फीसदी प्राकृतिक गैस का उपयोग किए जाने का लक्ष्य बनाया गया

नेटवर्क की स्थापना होगी। इस काम के लिए एक समग्र नीति बनाई जाएगी। इस काम के लिए इन्वेस्ट यूपी नोडल एजेंसी नामित किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रमुख सचिव अनिल

औद्योगिक विकास दर को बढ़ाने का भी जरिया

सिटी गैस वितरण ईकाई घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक उपयोग के लिए पाइपड नेचुरल गैस की आपूर्ति करेगी। इसके लिए सिटी गैस वितरण नेटवर्क की स्थापना होगी।

इसके अलावा सीएनजी स्टेशन के जरिए स्वचालित वाहनों की ईंधन के रूप में सीएनजी की आपूर्ति होगी। पत्र में कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम के कारण स्वचालित वाहनों से सिलेंडर के जरिए गैस की आपूर्ति खर्चीली व्यवस्था है। पाइप

लाइन के जरिए घर-घर गैस की आपूर्ति निर्बाध व मितव्ययी उपाय है। सिटी गैस वितरण परियोजना न केवल घरेलू खाना पकाने और आटो मोबाइल ईंधन के रूप में स्वच्छ व हरित ईंधन लाने का साधन है बल्कि यह राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ाने का भी जरिया बनेगा। ऊर्जा की मांग को पूरा करने व टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए ईंधन मिश्रण में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ाया जाना जरूरी है।

सागर ने संबंधित अधिकारियों व ग्रीन गैस लिमिटेड, सेंट्रल यूपी गैस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, गेल इंडिया, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम को पत्र भेजा है। केंद्र सरकार द्वारा देश के

प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक 6.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है।